हिन्दी प्रादेशिक समाचार

आकाशवाणी चंडीगढ़

(तिथि 25 मार्च 2026, समय 18:10 (10 मिनट)

- लोकसभा ने ध्वनि मत से वित्त विधेयक-2026 पारित किया।
- केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने पश्चिम एशिया संकट और उभरती चुनौतियों के इस दौर में विपक्ष की भूमिका की आलोचना की।
- केंद्रीय मंत्रिमण्डल ने संशोधित उड़ान योजना को 10 वर्ष की अवधि के लिए 28 हज़ार, 840 करोड़ रुपये के कुल परिव्यय के साथ लागू करने को मज़ूरी दी।
- केंद्र सरकार ने कहा- देश में पैट्रोल व डीज़ल पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध। किसी पैट्रोल पंप पर तेल की कोई कमी नहीं।
- हरियाणा सेवा का अधिकार आयोग एवं त्रिपुरा सरकार के बीच ऑटो अपील सिस्टम के उपयोग को लेकर समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए ।

****

लोकसभा ने ध्वनि मत से वित्त विधेयक 2026 पारित कर दिया है। यह विधेयक वित्त वर्ष 2026-2027 के लिए केंद्र सरकार के वित्तीय प्रस्तावों को लागू करने का प्रावधान करता है। सदन ने सरकार द्वारा प्रस्तावित संशोधनों को मंजूरी दे दी। आज सदन में वित्त विधेयक, 2026 पर हुई चर्चा का उत्तर देते हुए केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा कि सरकार सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों, किसानों तथा सहकारी समितियों को सशक्त बना रही है। श्रीमती सीतारामन ने कहा कि यह वित्त विधेयक मध्यम वर्ग पर केंद्रित है और सरकार ने 17 महत्वपूर्ण जीवन रक्षक दवाओं पर बुनियादी सीमा शुल्क से छूट दी है।

1- निर्मला सीतारामन

हमने 17 जीवन रक्षक दवाओं पर बुनियादी सीमा शुल्क से छूट दी है। क्या इससे छोटे परिवारों, आम नागरिकों को लाभ नहीं होगा जिनके परिवार के बुजुर्ग या सदस्य अस्पताल में भर्ती हैं और जिन्हें ये महंगी दवाएं खरीदनी पड़ती हैं?

पश्चिम एशिया संकट और उभरती चुनौतियों का जिक्र करते हुए वित्त मंत्री ने कहा कि सरकार इन चुनौतियों से निपटने और उनके प्रभाव को कम करने के लिए कदम उठा रही है। श्रीमती सीतारामन ने विपक्ष की आलोचना करते हुए कहा कि विपक्ष सरकार के साथ खड़े होने के बजाय गैर-जिम्मेदाराना कदम उठा रहा है और जनता को गुमराह कर रहा है।

****

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आज वर्ष 2026-27 से वर्ष 2035-36 तक दस वर्षों की अवधि के लिए 28 हजार आठ सौ 40 करोड़ रुपये के कुल परिव्यय के साथ संशोधित उड़ान योजना को लागू करने की मंजूरी दी। नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद मीडिया को जानकारी देते हुए सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि क्षेत्रीय हवाई कनेक्टिविटी में सुधार के लिए योजना के तहत उन स्थानों पर सौ हवाई अड्डों का विकास किया जाएगा, जहां अभी तक हवाई पट्टियां नहीं हैं। इससे दूसरे और तीसरे दर्जे के शहरों में आर्थिक विकास, व्यापार और पर्यटन को भी बढ़ावा मिलेगा और आम नागरिकों के लिए किफायती हवाई यात्रा को सुगम बनाया जा सकेगा। मंत्रिमंडल ने आव्रजन, वीजा, विदेशी पंजीकरण और ट्रैकिंग-आई.वी.एफ.आर.टी योजना को इस वर्ष पहली अप्रैल से 5 वर्ष के लिए जारी रखने को मंजूरी दी है। इसका उद्देश्य भारत में आव्रजन, वीजा जारी करने और विदेशियों के पंजीकरण से संबंधित कार्यों को आपस में जोड़ना और उन्हें सुव्यवस्थित करना है।

2-अश्विनी वैष्णव

****

****

केन्द्र सरकार ने कहा है कि देश में 36 करोड़ टन कच्चे तेल के शोधन की क्षमता है। पश्चिम एशिया में हाल के घटनाक्रम पर आज नई दिल्ली में अंतर मंत्रालय प्रेस वार्ता में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने लोगों से अफवाहों पर ध्यान न देने की अपील की।

3-सुजाता शर्मा

पीएनजी विस्तार पर उन्होंने कहा पिछले 25 दिनों में लगभग ढाई लाख नये पीएनजी कनेक्शन दिए गए हैं।

4-सुजाता शर्मा

****

****

भारत पेट्रोलियम और हिंदुस्तान पेट्रोलियम ने कहा है कि देश भर में ईंधन की कोई कमी नहीं है। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि एलपीजी, कच्चे तेल, पेट्रोल, डीजल और एविएशन टर्बाइन फ्यूल का पर्याप्त भंडार उपलब्ध है और आपूर्ति श्रृंखला बिना किसी रुकावट के सुचारू रूप से चल रही है। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया है कि कुछ क्षेत्रों में पेट्रोल और डीजल की कमी की अफवाहें पूरी तरह निराधार हैं।

****

****

सरकार ने उन खबरों और सोशल मीडिया पोस्ट का खंडन किया है, जिनमें दावा किया गया था कि प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के कनेक्शन के लिए एल पी जी रिफिल बुकिंग की समय-सीमा बदलकर 45 दिन कर दी गई है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने स्पष्ट किया कि ऐसा कोई बदलाव नहीं किया गया है। मंत्रालय ने आगे

कहा कि यह शहरी इलाकों में 25 दिन और ग्रामीण इलाकों में 45 दिन ही बनी रहेगी, चाहे कनेक्शन किसी भी तरह का हो।

****

प्रादेशिक सामाचार आकाशवाणी चंडीगढ़ से प्रसारित किए जा रहे हैं। हमारे बुलेटिनों और ताज़ा समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग- इन कर सकते हैं। यह समाचार हमारे यू- ट्यूब चैनल और एक्स हैंडल Akashvani News Chandigarh पर भी उपलब्ध हैं।

****

हरियाणा सेवा का अधिकार आयोग और त्रिपुरा सरकार के बीच ऑटो अपील सिस्टम अपनाने और इसके उपयोग को लेकर एक समझौता ज्ञापन हस्ताक्षरित किया गया है। प्रवक्ता ने बताया कि समझौते के अनुसार, आटो अपील सिस्टम का स्वामित्व पूर्ण रूप से हरियाणा सेवा का अधिकार आयोग के पास रहेगा और त्रिपुरा सरकार को इसका सीमित, गैर-विशिष्ट और गैर-हस्तांतरणीय उपयोग का अधिकार दिया जाएगा। यह प्रणाली केवल सरकारी और सार्वजनिक सेवा वितरण के उद्देश्यों के लिए ही उपयोग की जाएगी। उन्होंने स्पष्ट किया कि इस प्रणाली का किसी भी प्रकार का व्यावसायिक उपयोग नहीं किया जा सकेगा और बिना पूर्व अनुमति के किसी तीसरे पक्ष के साथ इसे साझा नहीं किया जाएगा। त्रिपुरा सरकार द्वारा प्रणाली के उपयोग के दौरान हरियाणा सेवा का अधिकार आयोग को स्रोत के रूप में उचित श्रेय देना अनिवार्य होगा।यह प्रणाली त्रिपुरा सरकार को निःशुल्क उपलब्ध कराई जाएगी।

****

उपायुक्त मोहम्मद इमरान रजा की अध्यक्षता में आज हुई जींद जिले की परिवेदना समिति की बैठक में कुल 14 शिकायते सुनवाई के लिए रखी गई। 6 शिकायतों का मौके पर ही निपटान कर दिया गया जबकि 8 शिकायतें लंबित रखी गईं। उपायुक्त ने

मीडिया से बातचीत में बताया कि रोहतक रोड पर गड्ढों को लेकर बार बार मिल रही शिकायतों का विशेष तौर पर संज्ञान लिया गया।

5- मोहम्मद इमरान रजा

****

आकाशवाणी कल से अपने सुबह के प्रसारण की शुरुआत राष्ट्रगान वंदे मातरम के पूर्ण संस्करण से करेगा। सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने कहा कि गृह मंत्रालय के हालिया दिशा निर्देश में राष्ट्रगान के छह श्लोकों को शामिल किया गया है। पूर्ण संस्करण की अवधि 3 मिनट 10 सेकंड है। प्रसारित होने वाला पहला संस्करण प्रसिद्ध हिंदी शास्त्रीय गायक पंडित चंद्रशेखर वाजे द्वारा राग देस में गाया गया है। मंत्रालय ने कहा कि संगीत विविधता को प्रदर्शित करने के लिए छह श्लोकों वाले वंदे मातरम के क्षेत्रीय संस्करण भी रिकॉर्ड किए जा रहे हैं। इन संस्करणों को संबंधित राज्यों में स्थित आकाशवाणी स्टेशनों द्वारा अपनाया जाएगा।

****

केन्द्रीय शिक्षा मंत्रालय ने परियोजना अनुमोदन बोर्ड की बैठक में वित्त वर्ष 2026-27 में कक्षा पहली से आठवीं तक के विद्यार्थियों को निःशुल्क पाठ्यपुस्तकें उपलब्ध कराने हेतु 45 करोड़ 5 लाख रुपये की राशि अनुमोदित की है। हरियाणा स्कूल शिक्षा परियोजना परिषद के प्रवक्ता ने बताया कि 15 अप्रैल तक पाठ्यपुस्तकों की आपूर्ति का कार्य पूर्ण किया जाएगा। उन्होंने बताया कि शिक्षा मंत्री महिपाल ढांडा के मार्गदर्शन एवं निगरानी में संबंधित फर्मों द्वारा अम्बाला, हिसार, कुरुक्षेत्र, पानीपत, पलवल, भिवानी एवं चरखी दादरी जिलों में कक्षा 1 से 8 तक की पाठ्यपुस्तकों की आपूर्ति जिला स्तर पर की जा चुकी है। निर्धारित समय-सीमा के भीतर सभी विद्यालयों तक पाठ्य पुस्तकों की आपूर्ति सुनिश्चित कर दी जाएगी। पाठ्यपुस्तकों के समयबद्ध वितरण को सुनिश्चित करने हेतु शिक्षा मंत्री का कार्यालय विभाग के साथ सतत समन्वय बनाए हुए है।